

#### ग्रसाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II-- लण्ड 3---उपलब्द (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं **141]** नई विल्ली, रशिवार, श्राग्री 2, 1970/श्रावण 11, 1892

No. 141 NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 2, 1970/SRAVANA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि दह ग्रज़ग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

### DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August 1970

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICE COMMISSION (CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRMAN AND MEMBERS) RULES, 1970.

- G.S.R. 1122.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Gevernment hereby makes the following rules, namely:—
- 1. Short-title.—These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Mcmbers) Rules, 1970.
  - 2. Definitions.-In these rules,-
    - (a) "Act" means the Monopolics and Restrictive Trude Practices Act, 1969 (54 of 1969);
    - (b) "Chairman" means the Chairman of the Commission;
    - (c) "Commission" means the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, established under section 5 of the Act;
    - (d) "form" means a form specified in the Schedule to these rules;
    - (c) "Judge" includes the Chief Justice, an acting Chief Justice, an Additional Judge and an acting Judge;

- (f) "mcmber" means a member of the Commission.
- 3. Remuneration, allowances, etc. of Chairman.—(1) A retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairman or member shall be paid such salary which together with his pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits shall not exceed the last pay drawn by him before retirement. He shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be.
- (2) Where the Chairman or member retires from service as a Judge of the Supreme Court or of a High Court during the term of office of such Chairman or member, he shall be paid for the period he serves as Chairman or member after retirement, such salary which, together with  $h_{\rm IS}$  pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits shall not exceed the last pay drawn by him before retirement.
- (3) A person, not being a serving or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairman shall be paid a salary of rupees three thousand five hundred per mensem and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to a Government officer of the first grade.
- 4. Remuneration, allowances of members.—A person, not being a serving or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, appointed as a member shall be paid a salary of rupees three thousand per mensem and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to a Government officer of the first grade.
- 5. Travelling and dally allowances.—(1) If the Chairman or a member is a serving or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to draw travelling allowance under the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, or as the case may be, the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956, in respect of journeys performed by him in connection with the work of the Commission at the rates as are admissible to a Judge of the Supreme Court, or the High Court.
- (2) If the Chairman or any member is not a serving or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to draw travelling allowance in respect of journeys performed by him in connection with the work of the Commission at the same rates as are admissible to a Government officer of the first grade.
- 6. Leave.—A person, not being a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, appointed as Chairman or member, shall be eligible to such leave as is admissible to an officer of the Government under the Revised Leave Rules, 1933;

Provided that where a Government officer to whom the Revised Leave Rules, 1933 are not applicable is appointed as a member, he shall be eligible for the grant of leave under the rules applicable to him before such appointment.

- 7. Oaths of office and of secrecy.—(1) Every person appointed to be the Chairman shall, before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and of secrecy before the President of India, in Form I and Form II respectively.
- (2) Every person appointed to be a member shall, before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and of secrecy before the Chairman in Form I and Form II respectively.

THE SCHEDULE

FORM I
(See Rule 7)

Form of oath of office for the Chalrman/member of the Monopolles and Restrictive Trade Practices Commission:—

"I. A. B., having been appointed as Chairman/member of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Con mission do swear in the name of God that I will Solemnly affirm

falthfully and conscientiously discharge my duties as Chairman/member to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will."

# FORM II (See Rule 7)

Form of oath of secrecy for Chairman/member of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission:—

"I, A. B., having been appointed as Chairman/member of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission do swear in the name of God that I will Solemnly affirm

not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman/member of the said Commission except as may be required for the due discharge of my duties as Chairman/member."

[No. F.1/2/70-M(P).] B. P. ROY, Officer on Special Duty.

## कम्पनी कार्य विभाग

### भ्रधिसूचना

नई दिल्ली, 1 श्रगस्त 1970

एकाधिकार तथा निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा म्रायोग (म्रध्यक्ष म्रौर सदस्य को सेवा की शर्ते) नियम, 1970

सा० का० वि० 1122 ---एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा श्रिधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, श्रर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम : ये नियम एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा श्रायोग (श्रध्यक्ष श्रौर सदस्य को सेवा की णर्ते) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।
  - 2. परिभाषाए .--इन नियमो मे---
    - (क) "श्रिधिनियम" मे एकाधिकार तथा निर्वेन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969
       (1969 का 54) श्रिभिनेत है;
    - (ख) "प्रध्यक्ष" में ग्रायोग का ग्रध्यक्ष ग्रभिप्रेत है ;
    - (ग) "श्रायोग" मे श्रधिनियम की धारा 5 के श्रधीन स्थापित एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा स्रायोग श्रभिप्रेत है;
    - (घ) ''प्ररूप'' में इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप श्रिभिप्रेत हैं;
    - (ङ) "न्यायाधीण" के श्रन्तर्गत मुख्य न्यायमृति, कोई कार्यकारी मुख्य न्याय मृति, कोई अपर न्यायाधीण, श्रीर कोई कार्यकारी न्यायाधीण है ;
    - (च) ''सदस्य'' मे ब्रायोग का सदस्य ग्रभिन्नेत है।
- 3. ग्राध्यक्ष के पारिश्रमि , भत्ते ग्राबि (1) श्रध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को ऐसर मम्बलम् संदत्त किया जाएगा

जो उसकी पेंशन धीर किसी अन्य प्रकार की निवृति प्रसृविधाओं के सपतुन्य पेणन सिहत उसके द्वारा सेवा निवृति से पूर्व लिए गए अन्तिम वेतन से अधिक नहीं होगा। वह ऐसे भनो और अन्य प्रसृविधाओं का हकदार होगा जैसा कि यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के सेवा कर रहे न्यायाधीण को अनुनेय है।

- (2) जब प्रध्यक्ष या मदम्य को, उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा में ऐसे प्रध्यक्ष ग्रीर सदस्य की पदावधि के दौरान निवृति हो तो निवृति के पश्चात् उसको उस कालावधि के लिए ऐसा सम्बलम् संदत्त किया जाएगा जो उसको पेशन ग्रीर किसी ग्रन्य प्रकार की निवृति प्रमुविधान्नों के समनुन्य पेशन महित उसके द्वारा सेवा निवृति से पूर्व लिए गए ग्रितिम वेतन से श्रिधक नहीं होगा ।
- (3) किसी व्यक्ति के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में सेशास्त या सेशा में निवृत न्यायाधीश न होने पर उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर प्रति मास तीन हजार पाच सौ रुपए का सम्बलम् संदत्त किया जाएगा और वह ऐसा भत्ता पाने का हकटार होगा जो प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी को श्रन्ज्ञेय हो ।
- 4. मंबस्यों का पारिश्रमिक भत्ता िकसी व्यक्ति के उच्चतन नरायालय में सेवारत या मेवा में निवृत न्यायाधीण न होने पर उसके सदस्य के खा में निवृति पर प्रति माप तीन हजार रुपए का सम्बल्ध सदल्य किया जाएगा और यह ऐसा भना पाने का हकदार होगा जो प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी को अनुझेय हो।
- 5. यात्रा स्रोर देनिक अते.—-यदि स्रध्यक्ष या सदस्य उच्चतम न्यायालय मे पा उच्च न्यायालय मे सेवारत या सेवा निवृत न्यायाधीण हो तो वह उच्चतम न्यायालय न्यायाधीण (यात्रा भता) नियम, 1959 के स्रधीन या ययास्थिति, उच्च न्यायालय न्यायाधीण (यात्रा भता) नियम, 1956 के स्रधीन उसके द्वारा स्रायोग के कार्य के सम्बन्ध मे की गई पावास्थी के निए उन दरा पर यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा जो उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाश्योग की स्रानुजय हो।
- (2) यदि श्रध्यक्ष या कोई सदस्य उच्चतम न्यायालय मे या उच्च न्यायालय मे सेवारत या सेवानिवृत न्यायाधीय न हो तो वह, उसके द्वारा श्रायांग के कार्य के सम्बन्ध मे की गई यात्राश्रा के लिए उन दरों पर यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा जो प्रथम श्रेणी के सरकारी श्रिधिकारी को श्रनुजैय हो।
- 6. **छट्टी** ---किसी व्यक्ति के उच्चतम न्यासालय में या उच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीश न होने पर, ग्रध्यक्ष या सदस्य के खा में नियुक्ति पर वह ऐसा छट्टी लेने का पान्न होगा जो पूनरीक्षित छट्टी नियम, 1933 के श्रधीन किसी सरकारी प्रशिकारी को प्रतक्षेय हो।

परन्तु जहां कोई ऐसा सरकारी प्रधिकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है जित्तकों पुनरीक्षित छुट्टी नियम, 1933 लागू नहीं है वह ऐसी नियुक्ति के पूर्व उसको लागू नियमों के प्रयोग छुट्टी पाने का पान होगा।

- 7. पद की स्रीर गोपनी (ता की शप्य.——(1) प्रध्यक्ष नियुक्त किया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्रपना पद ग्रहण करने के पूर्व कमशः प्ररूप I स्रीर II में भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, पद की स्रीर गोपनीयता की शप्य लेगा स्रीर हस्ताक्षरित करेगा।
- (2) सदस्य नियुक्त किया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व क्रमणः प्ररूप I भ्रौर प्ररूप II में अध्यक्ष के समक्ष पद की भ्रौर गोपनीयता की शपथ लेगा भ्रौर हस्ताक्षरित करेगा।

ग्रनुसूची

प्ररूप I

(नियम 7 देखें)

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा श्रायोग के श्रष्टयक्ष/सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप :---

"मैं, क ख, जो एकाधिकार तथा निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा श्रायोग में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त हुत्रा हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अध्यक्ष/सदस्य के रूप में भय या पक्षपात,

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा न करता

भनुराग का द्वेष के बिना, श्रपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान भीर निर्णय से भ्रपने कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक भीर शुद्ध श्रन्त:करण से निर्वहन करूंगा।"

### प्ररूप II

(नियम 7 देखें)

एकाधिकार तथा निर्धन्धनकारी व्यापार प्रथा श्रायोग के श्रध्यक्ष/सदस्य के लिए गोप-नीयता की शपथ का प्ररूप :--

"मै, क ख, जो एकाधिकार तथा निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा म्रायोग में ग्रध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त हुमा हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उक्त ग्रायोग के ग्रध्यक्ष/सदस्य के रूप में

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता

मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस श्रवस्था को छोड़ कर जब कि ऐसे श्रध्यक्ष/सदस्य के रूप में श्रपने कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना श्रपेक्षित हो, श्रन्य श्रवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।"

[सं॰ फा॰ 1/2/70-म(प)]

बी० पी० राय, विशेषाधिकारी।

